POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

बजट 2019

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अगस्त, 2019 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट रखा। उन्होंने बजट में अपनी जादूगरी का ताना-बाना बुनकर सभी वर्ग के लोगों को खुश करने का प्रयास किया है।

खासकर, किसानों के लिए कृषक कल्याण कोष और महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि कोष बनाने, निःशुल्क दवा योजना को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के लिए युवाओं को कर्ज देने और 75 हजार नौकरियों का ऐलान कर बजट को संवारा गया है।

बजट में ग्रामीण विकास और सभी बुनियादी जरूरतों को अहमियत दी गई है। बजट शहरी विरासत, मेट्रो-रिफाइनरी और नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जैसी कई योजनाओं पर केन्द्रित है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 का आम बजट प्रस्तुत किया। बजट में जीरो बजट फार्मिंग, किसानों की आय दोगुनी करने, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, स्टार्टअप और स्वरोजगार से रोजगार सृजन करने, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने और नई शिक्षा नीति लागू करने की बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

आयुष्मान योजना का बजट बढ़ाने, सामाजिक कल्याण को अहमियत देने तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का भी वादा बजट में शामिल है। बजट में कई सुधार भी सामने आए हैं, जो देश के आर्थिक और बहुआयामी विकास को नई दिशा देंगे।

मेरा मानना रहा है कि कुल मिलाकर दोनों बजट तभी अच्छे कहे जा सकेंगे, जब घोषणाएं वास्तविक रूप से धरातल पर उतरें और उनका समय पर सही क्रियान्वयन हो। इसके लिए समय का निर्धारण, ठोस नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधार बेहद जरूरी है। नहीं तो ये बजट भी पुरानी कई घोषणाओं व योजनाओं की तरह कागजी पुलिन्दा बन कर रह जाएंगे। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

आम ग्रामीण बजट के आंकड़ों को सही रूप से समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रखकर लाभान्वित हो सकें।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से किया सम्मानित

कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार वर्ष 2018 के लिए यह पुरस्कार 'कट्स' द्वारा *'गुड सेमेरीटन गाइडलाइनः चेलेन्जेज एण्ड वे फॉरवर्ड'* विषय पर आधारित राज्य स्तरीय समारोह में दैनिक भास्कर के पत्रकार चेतन कुमार मालवीय को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

चेतन कुमार जोधपुर जिले के बिलाड़ा गांव के निवासी है। उन्होंने वर्ष 2018 के लिए चयनित विषय 'किसानों की स्थिति' विषय पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर में अनेक रोचक एवं तार्किक स्टोरियां प्रकाशित कर आमजन में जागरूकता लाने एवं जनचेतना जागृत करने का काम किया है।

महिला लीडरशिप को दिया प्रोत्साहन

आम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला लीडरशिप को प्रोत्साहित किया है। स्वयं सहायता समूहों में शामिल महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इसके साथ ही जनधन खाते से 5000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट देने की अनुमति भी दी गई है। इससे महिलाएं लघु उद्योग या कोई व्यवसाय शुरू कर अर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी। महिलाओं की इस भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुनहरी होगी।

'नारी तू नारायणी' योजना शुरू होगी। एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव देगी। महिला केंद्रित पॉलिसी के तहत महिला लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास होगा।

प्रदेश के बजट में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए की प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी शक्ति योजना की घोषणा की गई है। इससे महिलाओं को उद्यम स्थापना, आधुनिक अनुसंधान के लिए सहायता तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जा सकेगी। राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यकों के बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी के समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 21 हजार रुपए दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

खेतों में सोलर प्लांट से बनेगी बिजली

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य विधानसभा में पेश किए गए बजट के अनुसार वर्ष 2019-20 में ऊर्जा विभाग के लिए कुल 30 हजार 1170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 11.41 प्रतिशत अधिक है। सौर और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वालों को अब और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। सौर व पवन ऊर्जा की नई नीति के तहत सोलर पैनल लगाना ज्यादा आसान होगा।

केंद्र सरकार की कुसुम योजना से प्रदेश को काफी फायदा होगा। इससे किसान खाली खेतों की जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर खुद बिजली पैदा कर सकेंगे। खेतों में सिंचाई वाले कुओं व ट्यूबवेल पर भी सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे किसानों को दिन में बिजली मिल सकेगी। नेट मीटरिंग के जरिए किसान अतिरिक्त बिजली को ग्रिड पर बेच भी सकेंगे। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होगी। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल परिस्थितियां है, इसका भी लाभ मिलेगा।

नजर आई गांवों पर खास मेहरबानी

आम बजट में ग्रामीण विकास पर खास ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट के मुताबिक 2022 तक ग्रामीणों को पक्के घर मुहैया कराने का लक्ष्य है। पीएम आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गांवों में पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्फूर्ती योजना के तहत 50 हजार कारीगरों, शिल्पकारों को फायदा मिलेगा। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार का उद्देश्य अंत्योदय है, यही वजह है कि गरीब, किसान व गांवों से संबंधित सभी योजनाओं में बजट बढ़ाया गया है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर 191870 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत 10000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गांव के हर परिवार के पास 2022 तक बिजली और एलपीजी होगी।

प्रदेश के बजट में डामर सड़क से वंचित 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को अगले चार साल में सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4000 से अधिक आबादी वाले गांवों में पाइप लाइन से शुद्ध पीने का पानी घरों तक पहुंचेगा। पेयजल हेतु 1454 करोड़ रुपए की नई योजना बनाई है। प्रदेश के गांवों के लिए भी मास्टर प्लान बनेगा इससे गांवों में कई सहूलियतें मिलेंगी।

आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ कवर

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 19 फीसदी का इजाफा कर जन स्वास्थ्य को खास अहमियत दी है। स्वास्थ्य का बजट अब 62 हजार 659 करोड़ रुपए हो गया है। आयुष्मान योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। योजना के तहत 10.74 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 34.97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसके तहत 1.5 लाख सब-सेंटर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 2022 तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में बदला जाएगा। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन स्वास्थ्य के लिए बजट में 12750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें अब किडनी, हार्ट और कैंसर की 104 नई दवाइयों को शामिल किया गया है। कई बीमारियों की जांचें भी मुफ्त की गई हैं। गली-मोहल्लों में 200 नए जनता क्लिनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इन्हें निःशुल्क दवा योजना से जोड़ा जाएगा।

किसानों की दोगुनी आय, बनेंगे आत्मनिर्भर

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कृषि और संबंधित कार्यों पर सरकार इस वित्त वर्ष में 1.51 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह पिछले बजट की तुलना में दो गुना से भी ज्यादा है। कृषि, सिंचाई, फसल बीमा, मूल्य समर्थन समेत कई योजनाओं में बजट आवंटन बढ़ाया गया है। नए मॉडल के जरिए जीरो बजट फॉर्मिंग पर पूरा जोर रहेगा।

किसानों की पेंशन के लिए 900 करोड़, पीएम-आशा योजना के लिए 1500 करोड़ और किसान सम्मान के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। सिंचाई योजना में 253 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर 9680 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे, जिससे खेती-किसानी कॉरपोरेट तरीके से हो सकेगी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रदेश के बजट में 1000 करोड़ का कृषक कल्याण कोष बनाने और उससे किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने की घोषणा की गई है। जीरो बजट नेचुरल फॉर्मिंग पर बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही की 36 ग्राम पंचायतों में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि के लिए बहुउपयोगी व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। बजट में 10 लाख किसानों को फसली ऋण वितरण के लिए 16 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 700 भंडारों का निर्माण कराया जाएगा। पशुपालन को बढ़ावा दिया गया है, इस साल 400 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाएंगे।

अब हुनर से पनपेंगे रोजगार के अवसर

केंद्र सरकार के बजट में कौशल प्रशिक्षण के जरिए स्वयं का रोजगार स्थापित करने पर ज्यादा बल दिया गया है। इसके लिए 557 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार 100 इन्क्यूबेटर्स खोलेगी। इनके जरिए 75 हजार कुशल उद्यमियों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 80 आजीविका बिजनेस इन्क्यूबेटर और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्यूबेटर होंगे। स्फूर्ति योजना के तहत गांवों में पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 नए क्लस्टर्स बनेंगे जिनमें बांस, शहद और खादी जैसे उद्योगों पर खास फोकस होगा।

स्टेंड अप इंडिया और स्टार्ट अप नीति के तहत उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने के दीर्घकालीन उपाय किए जाएंगे। बजट में मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का आंवटन किया गया है, जो कि पिछले साल से 5000 करोड़ रुपए ज्यादा है। तकनीकी शिक्षा का बजट तीन गुना बढ़ाकर 950 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे मिडिल क्लास युवा को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में इस साल 75 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी पांच वर्षों में कुल 1000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। योजना के तहत इस वर्ष 25 हजार युवाओं को इससे लाभान्वित किया जाएगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाएगी बदलाव

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को सर्वोत्तम वैश्विक शिक्षा प्रणाली बनाने के मकसद से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जा रही है। बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 56537 करोड़ एवं उच्च शिक्षा के लिए 38317 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षा में कई नवाचार होंगे, उच्च शिक्षा आयोग व रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। रोजगारपरक व ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा में खेलों को भी प्राथमिकता दी गई है।

प्रदेश के बजट में शिक्षा के लिए 19563 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के स्कूलों का ढांचा सुधार कर शिक्षा की नींव को मजबूत बनाया जाएगा।

प्रदेश में इस साल 50 नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे, 60 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 100 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक एवं 500 माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा।

स्कूलों में मिड-डे-मील पर 1418 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उच्च शिक्षा के तहत पूर्व सरकार के डी-नोटिफाई किए आठ कॉलेजों को पुनः शुरू किया जाएगा।

इस बार भी नहीं बदला आयकर स्लैब

उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बजट में आयकर स्लैब बदल कर करदाताओं को राहत दी जाएगी। लेकिन आयकर स्लैब नहीं बदला गया है। हालांकि 5 लाख रुपए तक की करयोग्य आय करमुक्त रहेगी। करदाता कर बचत के सभी उपाय करेगा तो उसकी 12.25 लाख रुपए तक की आय करमुक्त हो सकती है।

वित्तमंत्री ने बजट में धारा 80(ग) के अंतर्गत आने वाली बचत के लिए कटौती की सीमा एक लाख से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपए कर दी है। वहीं चिकित्सा बीमा के लिए कटौती की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 25000 रुपए कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 20 हजार से बढ़ाकर सीधे 50 हजार रुपए की गई है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी इसमें 25 हजार रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

वरिष्ठ नागरिकों की बचत पर और लाभ देते हुए उनकी जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज पर 50 हजार रुपए की कटौती की गई है। उनके लिए गंभीर बीमारियों पर चिकित्सा व्यय के लिए कटौती की सीमा को भी 60 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर